RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 199
दि. 20.11.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.
Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

योगी सरकार ने कर दी किसानों की मौज! 95 नई नहर परियोजनाओं को मंजूरी, 9 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्वांचल, तराई, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की सिंचाई की दिक्कत दूर करने के लिए 95 नई नहर परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में एक बड़ा फैसला लिया. बैठक में सीएम योगी ने नहर प्रणाली को आधुनिक और सक्षम बनाने के उद्देश्य से कुल 95 नई परियोजनाओं को हरी झंडी दी. इन परियोजनाओं पर 39453.39 लाख रुपये की लागत आएगी और इसके पूर्ण होने पर 36 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता फिर से स्थापित हो जाएगी. इससे करीब 9 लाख किसानों और ग्रामीण आबादी को सीधा लाभ मिलने की संभावना है. साथ ही विभागीय 273 हेक्टेयर भूमि को भी संरक्षित किया जा सकेगा.

योगी सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्य तय समय सीमा में और उच्चतम गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं केवल निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये प्रदेश के जल प्रबंधन, कृषक हित, कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का महत्वपूर्ण आधार बनेंगी. सरकार का लक्ष्य है कि सिंचाई के अभाव में प्रदेश का कोई भी किसान अपनी फसल को नुकसान न झेलने पाए.

95 परियोजनाओं के मुख्य बिंदु

बैठक में विभाग ने बताया कि स्वीकृत 95 परियोजनाओं में नहरों के गैप्स भरने, नई कंक्रीट संरचनाओं, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, साइफन,

फॉल संरचनाओं और क्षतिग्रस्त कुलाबों के पुनर्निर्माण को शामिल किया गया है. आंतरिक एवं बाहरी सेक्शनों का सुधार, लाइनिंग कार्य, पुल-पुलियों का निर्माण एवं मरम्मत भी योजनाओं का हिस्सा हैं. नहर पटरियों पर खड़ंजा निर्माण, निरीक्षण भवनों और कार्यालयों के सुधार और नहरों पर स्थित पनचक्कियों के जीर्णोद्धार को भी प्राथमिकता दी गई है.

इन परियोजनाओं से विशेष रूप से पूर्वांचल, तराई, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ पहुंचेगा, जहां सिंचाई नेटवर्क को और अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी.

मुख्यमंत्री ने विभागीय अनुपयोगी भूमि के सर्वे और उसके बेहतर उपयोग के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए. इसके साथ ही उन्होंने आगामी वर्ष के लिए बाढ़ प्रबंधन तैयारियों को जनवरी से ही शुरू करने और जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में विस्तृत योजना बनाने पर जोर दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की 21वीं किस्त, 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिले 2-2 हजार रुपये

नई दिल्ली (जीएनएस)। पीएम किसान योजना के तहत आज 21वीं किस्त जारी की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किस्त जारी की। केंद्र सरकार की वैसे तो कई योजनाएं हैं जिनकी काफी चर्चा रहती हैं और जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। पर सबसे ज्यादा चर्चित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ही है। मौजूदा समय में इस योजना से करोड़ किसान जुड़े हैं।

इस पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ किसानों को मिलता है और इसी क्रम में इस बार करोड़ों किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त के पैसे हस्तांतरित किए। कोयंबटूर में आयोजित कार्यक्रम से ये किस्त जारी की गई। ऐसे में अगर आप भी योजना के लाभार्थी हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में किस्त के पैसे आए हैं या नहीं।

किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...

कुल 21 किस्त हो चुकी हैं जारी

पीएम किसान योजना के तहत अब तक कुल 21 किस्त जारी हो चुकी है। जहां 20वीं किस्त बीती 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी, तो वहीं 21वीं किस्त आज यानी 19 नवंबर 2025 को जारी हुई। किसानों के लिए ये बेहद खास समय होता है, जब उन्हें किस्त दी जाती है। हर बार केंद्र सरकार किस्त के रूप में किसानों की आर्थिक मदद करती है।

अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपके बैंक खाते में भी 2-2 हजार रुपये भेजे गए होंगे? पीएम किसान योजना से जुड़न वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। इसी क्रम में 21वीं किस्त में भी 2-2 हजार रुपये दिए गए।

पीएम किसान योजना की किस्त जारी होने के बाद सरकार द्वारा लाभार्थियों को मैसेज भेजा जाता है। इसमें जानकारी होती है कि बतौर लाभार्थी आपके बैंक खाते में किस्त के पैसे भेज दिए गए हैं

अगर आपको ये मैसेज नहीं आता है, तो आपको बैंक की तरफ से भी किस्त का मैसेज आता है जिसमें बताया होता है कि आपके खाते में 2 हजार रुपये आए हैं

आपके पास अगर मैसेज नहीं आया है और आपके पास अकाउंट का डेबिट कार्ड है, तो आप अपने नजदीकी एटीएम जाकर भी ये चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में 21वीं किस्त के पैसे आए हैं या नहीं।

लोक सभा अध्यक्ष ने संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में श्रीमती इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की

(जीएनएस)।

नई दिल्ली; 19 नवंबर, 2025: लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर आज संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री किरेन रिजिजू; राज्य सभा में विपक्ष के नेता, श्री मल्लिकार्जुन खरगे; लोक सभा में विपक्ष के नेता, श्री राहुल गांधी; संसद सदस्यों और पूर्व सदस्यों ने इस अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

लोक सभा के महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह और राज्य सभा के महासचिव, श्री पी.सी. मोदी ने भी

श्रीमती गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, श्री आर. वेंकटरमन ने 19 नवंबर 1987 को संविधान सदन (तत्कालीन संसद भवन) के केन्द्रीय कक्ष में किया था।

आंध्रप्रदेश के पुट्टपर्थी में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साईं राम के दिव्य मंत्रों के बीच आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचे जहां उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

प्रधानमंत्री ने प्रशांति निलयम के साईं कुलवंत हॉल में श्री सत्य साईं बाबा को श्रद्धांजलि दी और फिर दर्शन

के लिए ओंकार हॉल गए। उन्होंने कहा कि इन पवित्र स्थलों पर होना श्री सत्य साईं बाबा की असीम अनुकम्पा और मानवता के उत्थान के लिए आजीवन प्रतिबद्धता का स्मरण कराता है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री सत्य साईं बाबा का निःस्वार्थ सेवा का संदेश लाखों-करोड़ों लोगों को निरंतर मार्गदर्शित और प्रेरित कर रहा है।

राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से यह स्मरण रखने का आह्वान किया कि सच्ची प्रगति का मापदंड केवल आविष्कार नहीं, बल्कि समाज में इसकी सकारात्मक उपयोगिता है

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (19 नवंबर, 2025) नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान झ एनआईटी - दिल्ली के पांचवें दीक्षांत समारोह में गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि एनआईटी दिल्ली ने बहुत कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि संस्थान आधुनिक अवसंरचना और शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि बहु-विषयी शिक्षा, नवोन्मेष, अनुसंधान, उद्यम क्षेत्रों के साथ सहयोग और कौशल-जनित शिक्षा को बढ़ावा देकर, यह संस्थान छात्रों को भविष्योन्मुखी आवश्यकताओं के लिए सक्षम बना रहा है।

राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि एनआईटी दिल्ली ने उद्यमशीलता और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्ट-अप केंद्र स्थापित किया है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनके नवीन स्टार्ट-अप के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर मिल रहे हैं। यहां एक इनक्यूबेशन सेंटर (उद्भवन केंद्र) भी स्थापित किया जा रहा है, जो नवीन विचारों को व्यवहार्य व्यवसायों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेगा। श्रीमती मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह के प्रयास से छात्र सशक्त बनेंगे और स्वरोजगार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर पूरे विश्वास के साथ अग्रसर हैं। यह प्रतिबद्धता आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं, बल्कि समावेशी विकास, तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास भी इसमें शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया, सुगम्य भारत अभियान और उन्नत भारत अभियान जैसी सरकार की पहल दर्शाती है कि जनभागीदारी के साथ भारत अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है।

प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी बहादुरी और पराक्रम की कहानी भारतीयों में जोश और जुनून भरती रहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए उनके बलिदान और संघर्ष को कभी नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री ने पर लिखा; 'मां भारती की अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आजादी के पहले संग्राम में उनकी वीरता और पराक्रम की कहानी आज भी देशवासियों को जोश और जुनून से भर देती है। मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके त्याग और संघर्ष को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता।

मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के करकमलों से 11.68 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न कृषि सहायता के मंजूरी पत्रों का वितरण

गांधीनगर, 19 नवंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य के किसानों पर हाल ही में आई असाधारण बेमौसम बरसात की विपदा से हुए नुकसान से उन्हें उबारने के लिए इस डबल इंजन सरकार ने बहुत ही तेजी से 10 हजार करोड़ रुपए का उदारतम सहायता पैकेज दिया है।

मुख्यमंत्री ने यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर से देश के किसानों के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने के अवसर पर गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कही। इस मौके पर राज्य के किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 21वीं किस्त के अंतर्गत 18 हजार करोड़ रुपए की सहायता राशि

हस्तांतरित की। इस सहायता के तहत गुजरात के 49.31 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए 986 करोड़ रुपए मिले।

गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी और कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा ने पीएम-किसान सम्मान निधि के साथ ही 11.68 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न कृषि सहायताओं के मंजूरी पत्रों का वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेन्ज की चुनौतियों से निपटने के लिए ह्यएक पेड़ मां के नाम' और प्राकृतिक कृषि जैसे अभियानों के माध्यम से ग्रीन कवर बढ़ाकर सुरक्षा प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन युक्त खेती से बिगड़ रहे जमीन और मानव के स्वास्थ्य को बचाने के उपाय के रूप में प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक कृषि को अपनाने का जो विचार दिया है, वह भविष्य की पीढ़ी के स्वस्थ एवं तंदुरुस्त जीवन तथा जमीन की उर्वरता बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगा।

पाकिस्तान ने कबूला- हमने करवाया लाल किले के बाहर हमला, अब क्या करेगी मोदी सरकार?

(जीएनएस)। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की घटना को मोदी सरकार आतंकी हमला करार कर चुकी है। वहीं अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक पाकिस्तानी राजनेता चौधरी अनवरुल हक ने कबूला है कि दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए हमले में पाकिस्तान की सीधी भूमिका थी।

इस नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सदन में खड़े होकर सीना ठोककर ये दावा करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की विधानसभा में अनवरुल हक ने कहा कि हमने पहले ही भारत को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

पाकिस्तानी नेता हक ने दावा किया, "मैंने पहले कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान को खून बहाते रहेंगे, तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक जवाब देंगे। अल्लाह के फजल से, हमने इसे अंजाम दिया है... हमारे लड़ाकों ने यह किया है।"

उसने दोहराया कि उन्होंने ऐसे हमले की भविष्यवाणी की थी, और डींग मारते हुए कहा कि "हमारे बहादुर जवानों ने यह कर दिखाया है।" उन्होंने यहां तक कहा कि भारत हताहतों का हिसाब लगाने में असमर्थ था।

हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक हक के इस बयान पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में अलग से संकेत दिया था कि इस्लामाबाद भारत के साथ "पूरी तरह से युद्ध" की संभावना को खारिज नहीं कर सकता है, और कहा कि बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर बलूचिस्तान में अस्थिरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है, एक आरोप जिसे नई दिल्ली खारिज करती है, इसे पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद से ध्यान भटकाने का प्रयास बताती है।

भारत ने प्रांत के भीतर हिंसा में किसी भी संलिप्तता से लगातार इनकार किया है।

दिल्ली में किसने करवाया कार ब्लास्ट?

इस बीच, खुफिया जानकारी के मुताबिक, लाल किले पर हुए बम धमाके में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने का पता चला है। यह हमला हुंडई आई20 गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल भरकर किया गया था। जैश-ए-मोहम्मद कई पाकिस्तान-समर्थित चरमपंथी समूहों में से एक है। इस आतंकी संगठन और हमले के पीछे की आतंकी सेल के बीच संबंध स्थापित हुए हैं।

तीन साल तक पुलिस के रडार से बचे रहे

वहीं रणनीति में बदलाव पर चर्चा के लिए उच्च-स्तरीय सुरक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। एक बैठक के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई और इसे स्थानीय आतंकवादी गतिविधि को चिन्हित करने के लिए कैसे बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनों के समय में संशोधन

मुंबई,

पश्चिम रेलवे की दो जोड़ी ट्रेनों के ठहराव के समय में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है।

1. ट्रेन संख्या 10115 बांद्रा टर्मिनस – मडगाँव एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 10115 बांद्रा टर्मिनस – मडगाँव एक्सप्रेस के ठहराव का समय संशोधित कर रत्नागिरी स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 16:05/16:10 बजे के बजाय 15:35/15:40 बजे कर दिया गया है।

कणकवली स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 18:40/18:42 बजे के बजाय 18:00/18:02 बजे होगा। सिंधुदुर्ग स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 19:00/19:02 बजे के बजाय 18:20/18:22 बजे होगा।

2. ट्रेन संख्या 19259 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ – भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 19259 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ – भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस के ठहराव का समय संशोधित कर सिंधुदुर्ग स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 12:20/12:22 बजे के बजाय 12:50/12:52 बजे कर दिया गया है।

ट्रेनों के ठहराव और समय के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर रेलवे मंडल से होकर चलने वाली 4 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के गांधीनगर जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास और बड़े स्तर पर उन्नयन कार्य के मद्देनजर 9 नवंबर से 13 दिसंबर, 2025 तक 35 दिनों का ब्लॉक लिया गया है, जिसके कारण भावनगर मंडल की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. पोरबंदर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19269 पोरबंदर–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से 12 दिसंबर, 2025 तक परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा–रींगस–रेवाड़ी स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी और यह ट्रेन रींगस, नीम का थाना और नारनौल स्टेशनों पर रूकेगी।

2. पोरबंदर से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20937 पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 09 दिसंबर, 2025 तक परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा–रींगस–रेवाड़ी स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी और यह ट्रेन रींगस, नीम का थाना और नारनौल स्टेशनों पर रुकेगी।

3. दिल्ली सराय रोहिल्ला से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20938 दिल्ली सराय रोहिल्ला–पोरबंदर एक्सप्रेस 24 नवंबर, 2025 से 8 दिसंबर, 2025 तक परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी और यह ट्रेन नारनौल, नीम का थाना और रींगस स्टेशनों पर रुकेगी।

4. 25 नवंबर, 2025 को अयोध्या कैंट से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19202 अयोध्या कैंट–भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया भरतपुर–कोटा–आणंद–अहमदाबाद–विरमगाम स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी और यह ट्रेन सवाई माधोपुर, कोटा, भवानी मंडी, शामगढ़, नागदा, रतलाम, दाहोद, गोधरा और आणंद स्टेशनों पर रुकेगी।

वडोदरा मंडल ने भारतीय रेलवे पर पहली बार ई–नीलामी नवाचार के माध्यम से "अपनी तरह का पहला" वेयरहाउसिंग अनुबंध किया

वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग ने गैर–किराया राजस्व (नॉन फेयर रिवेन्यू) पहल को उल्लेखनीय बढ़ावा देते हुए, भारतीय रेलवे पर पहली बार ई–नीलामी नवाचार के माध्यम से एक वेयरहाउस सुविधा के लिए "अपनी तरह का पहला" अनुबंध सफलतापूर्वक किया है। इस पहल के तहत वडोदरा स्टेशन पार्सल कार्यालय के पास पहले से खाली पड़े स्थान की पहचान कर, उसका प्रभावी सदुपयोग किया गया और एक गैर–निष्पादित परिसंपत्ति को रेलवे के लिए एक आकर्षक राजस्व स्रोत में बदल दिया गया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंडल के वाणिज्य विभाग ने यह उपलब्धि ई–नीलामी मॉड्यूल में

एक विशेष श्रेणी के निर्माण के माध्यम से हासिल की गई। इस तरह के नवाचार से भारतीय रेलवे में अधिक लचीले परिसंपत्ति मुद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। इस अनुबंध का मूल्य तीन वर्षों की अवधि के लिए 24.33 लाख रुपये है, जो रेलवे के अपने संसाधनों के मुद्रीकरण को अधिकतम करने के उद्देश्य की दिशा में एक सफल कदम है।

यह समर्पित वेयरहाउसिंग सुविधा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करती है, जिससे पार्सल यातायात की अधिक मात्रा आकर्षित होने की उम्मीद है। स्टेशन पर एक निर्दिष्ट भंडारण क्षेत्र उपलब्ध कराने से, प्लेटफार्मों पर पार्सल पैकेजों के रखने में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी। साथ ही वडोदरा स्टेशन पर पहले से खाली पड़े क्षेत्र की साफ – सफाई भी बेहतर ढंग से हो सकेगी, जिससे रेलवे के रखरखाव की लागत में कमी आएगी। इस स्थान के उपयोग से अनधिकृत अतिक्रमणों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और समग्र स्टेशन सुरक्षा में वृद्धि होगी। यह पहल प्रभावी स्थान प्रबंधन के लिए एक आदर्श उदाहरण है।

केंद्रीय संचार राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बाकू में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया

बाकू में भारतीय प्रवासियों से भारत के भविष्य को मार्गदर्शन, निवेश और आकार देने का आह्वान किया

विदेश में भारत को सशक्त बनाना: केंद्रीय राज्यमंत्री ने प्रवासियों से संबंधों को मजबूत करने और विकास को गति देने का आग्रह किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सोमवार शाम बाकू में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी। उन्होंने 1,000 से अधिक व्यक्तियों की उस सभा की सराहना की, जिसमें अंतरराष्ट्रीय तेल एवं गैस, आतिथ्य और कमोडिटी ट्रेडिंग क्षेत्रों के पेशेवर तथा 380 विश्वविद्यालय के छात्र शामिल थे।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने समुदाय की एकता की सराहना की, जो भारतीय अजरबैजान संघ, अजरबैजान तेलुगु संघ, बाकू तमिल संघम और

अजरबैजान के भारतीय छात्रसंघ जैसे कई संगठनों की स्थापना में परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि यह सभा एक आधुनिक, लचीले और महत्वाकांक्षी भारत का चेहरा प्रस्तुत करती है, जो अपने देश से हजारों मील दूर होने के बावजूद अपनी विरासत में गहराई से समाया हुआ है।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने भारत के उभरते परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए डिजिटल नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण और आर्थिक गतिशीलता में देश की प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रवासी समुदाय भारत की यात्रा का अभिन्न अंग बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। उनके निवेश अवसर पैदा करते हैं और उनके बच्चे संस्कृतियों के बीच भविष्य के सेतु का काम करते हैं।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने युवाओं से अपनी दोहरी पहचान को गर्व से अपनाने और भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने समुदाय से जुड़े रहने, ज्ञान साझा करने, युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन करने और भारत की विकास गाथा में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रवासी समुदाय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अपनी बात का यह कहते हुए समापन किया कि भारत के द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं।

ट्राई ने आरबीआई, सेबी और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित बीएफएसआई क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा 1600–सीरीज को चरणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए निर्देश जारी किए

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार से एक निर्देश जारी किया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा '1600' नंबरिंग श्रृंखला को अपनाने की अंतिम तिथियों को अनिवार्य किया गया है। यह निर्देश उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने, स्पैम पर अंकुश लगाने और वॉयस कॉल के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

ट्राई की नियामक पहल के जवाब में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र की संस्थाओं और सरकारी संगठनों को '1600' नंबरिंग श्रृंखला आवंटित की है ताकि उनकी सेवा और लेन–देन संबंधी कॉलों को अन्य वाणिज्यिक संचारों से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके। यह श्रृंखला नागरिकों को विनियमित वित्तीय संस्थानों से आने वाली वैध कॉलों की विश्वसनीय पहचान करने में सक्षम बनाएगी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को श्रृंखला के असाइनमेंट और नंबरिंग संसाधनों के आवंटन के बाद ट्राई ने बीएफएसआई क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा 1600 श्रृंखला को अपनाने के लिए टीएसपी और बीएफएसआई क्षेत्र के नियामकों के साथ नियमित रूप से काम किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 485 संस्थाओं ने पहले ही 1600 श्रृंखला को अपना लिया है और कुल 2800 से अधिक नंबरों की सदस्यता ले ली है। हितधारकों के साथ ट्राई की बातचीत के आधार पर यह माना जाता है कि अब समय आ गया है कि इस अभ्यास को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए

बिहार चुनाव, 2025: चुनाव आयोग ने सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित की

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधान सभा के 2025 के आम चुनाव के लिए 14 सांख्यिकीय रिपोर्टों का एक सेट प्रकाशित किया है।

सांख्यिकीय रिपोर्ट में कई चरों को शामिल किया गया है, जैसे राज्य स्तरीय और विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं का विवरण, मतदान केंद्रों की संख्या, राज्य/विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता मतदान, विधानसभा क्षेत्रवार महिलाओं की भागीदारी, पाटीवार वोट शेयर, लिंग आधारित मतदान भागीदारी, निर्वाचन क्षेत्र डेटा सारांश रिपोर्ट, राष्ट्रीय/राज्यीय दलों/आरयूपीपी का प्रदर्शन, विजयी उम्मीदवारों का विश्लेषण, निर्वाचन क्षेत्रवार विस्तृत परिणाम तथा अन्य विवरण।

सांख्यिकीय रिपोर्टों का प्रकाशन, शिक्षाविदों, शोधकताओं और आम जनता सहित सभी हितधारकों के लिए चुनाव संबंधी आंकड़ों की पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ईसीआई की एक स्व–प्रेरित पहल है।

ये रिपोर्ट बिहार चुनाव समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर प्रकाशित की गई हैं, जबकि पहले रिपोर्ट प्रकाशित होने में कई सप्ताह या महीने लग जाते थे।

सांख्यिकीय रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:

मुख्य अंश

एसी वाइज मतदाता जानकारी

एसी वार उम्मीदवार डेटा सारांश

मतदाता डेटा सारांश

विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या

महिला उम्मीदवारों का व्यक्तिगत प्रदर्शन

भाग लेने वाले राजनीतिक दलों की सूची

निर्वाचन क्षेत्र डेटा सारांश रिपोर्ट

सफल उम्मीदवारों की सूची

उम्मीदवार डेटा सारांश

विस्तृत परिणाम

राजनीतिक दलों का प्रदर्शन

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का विवरण ईसीआईनेट ऐप पर उपलब्ध इंडेक्स कार्ड में देखा जा सकता है– श वर्तमान चुनाव श इंडेक्स कार्ड।

ये सांख्यिकीय रिपोर्टें केवल शैक्षणिक और शोध उद्देश्यों के लिए इंडेक्स कार्ड में भरे गए द्वितीयक आंकड़ों से तैयार की जाती हैं। प्राथमिक आंकड़े संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा बनाए गए वैधानिक प्रपत्रों में होते हैं और वैधानिक प्रपत्रों में रखे गए आंकड़े अंतिम होते हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता के लिए इजराइल का दौरा करेंगे

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, इजराइल के अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री श्री नीर बरकत के निमंत्रण पर 20 से 22 नवंबर 2025 तक इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है और व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं निवेश के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दशार्ती है। श्री गोयल के साथ सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और स्टार्ट–अप इंडिया का एक 60 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा।

श्री गोयल अपनी इस यात्रा के दौरान इजराइल के शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्च–स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। अपने इजराइली समकक्ष, अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री श्री नीर बरकत के अलावा, वह कुछ अन्य मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। यह चर्चा व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, कृषि, जल, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, जीवन विज्ञान, बुनियादी ढांचे, उन्नत विनिर्माण जैसे

प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा स्टार्ट–अप सहित दोनों देशों के व्यवसायों के बीच बेहतर सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। प्रस्तावित भारत–इजराइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की प्रगति की समीक्षा भी की जा सकती है।

श्री गोयल भारत–इजराइल व्यापार फोरम में भाग लेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के प्रमुख व्यापारिक संघ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान उद्घाटन और पूर्ण समापन सत्र, तकनीकी चचाएं और बिजनेस–टू–बिजनेस बैठकें शामिल होंगी। इनका उद्देश्य वाणिज्यिक साझेदारी का विस्तार करना, निवेश को बढ़ावा देना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों के अवसरों की पहचान करना है। इसी दौरान दोनों पक्षों के प्रमुख सीईओ के साथ उच्च–स्तरीय सीईओ मंच का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कृषि, विलवणीकरण और अपशिष्ट जल उपचार, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी, बुनियादी ढांचे आदि क्षेत्रों की प्रमुख इजराइली कंपनियों के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे तथा प्रमुख इजराइली निवेशकों के साथ बातचीत करेंगे।

तेल अवीव में आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा, श्री गोयल का प्रमुख संस्थानों और नवाचार केंद्रों का दौरा भी शामिल है, जो इजराइल के अत्याधुनिक तकनीकी इकोसिस्टम की जानकारी प्रदान करेंगे। भारतीय समुदाय और भारतीय मूल के व्यापारिक नेताओं के साथ मुलाकात सहित सांस्कृतिक और सामुदायिक संपर्क भी इस यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

इस यात्रा से भारत और इजराइल के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए अवसर तैयार होने की उम्मीद है।

भारतीय डाक ने पहली बार जेन–जी थीम पर आधारित नए सिरे से तैयार कैंपस डाकघर का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

संचार मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय डाक ने अपने आधुनिकीकरण अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आईआईटी दिल्ली में नए सिरे से तैयार देश का पहला जेन–जी (ॠल्ल)झथीम आधारित डाकघर शुरू किया है। यह पहल संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के डाकघरों को जीवंत, युवा–केंद्रित स्थानों में बदलने की दूरदर्शिता को दिखाता है, जो आज के छात्रों और युवा नागरिकों के साथ मेल खा सकें।

आईआईटी दिल्ली का यह नया कैंपस डाकघर शैक्षणिक परिसरों में डाक सेवाओं से जुड़ाव के पूरी तरह नए मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है। छात्रों के सहयोग से तैयार किया गया यह केंद्र आधुनिक सौंदर्यशास्त्र, वाई–फाई सक्षम क्षेत्र, आईआईटी फाइन आट्‌र्स सोसाइटी की क्रिएटिव ग्रैफिटी और कलाकृतियों, तथा स्मार्ट सर्विस टचपॉइंट्स जैसे– क्यूआर–आधारित पार्सल बुकिंग और छात्रझ अनुकूल स्पीड पोस्ट छूट जैसी सुविधाओं से लैस है।

आईआईटी दिल्ली परिसर में आईआईटी हौज खास के नए सिरे से तैयार डाकघर का उद्घाटन किया गया

यह बदलाव राष्ट्रीय स्तर की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत 15 दिसंबर 2025 तक शैक्षणिक परिसरों में स्थित 46 डाकघरों को नए सिरे से तैयार किया जाना निर्धारित है।

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है छात्रों की सक्रिय भागीदारी, जिसमें भारतीय डाक छात्रों को ब्रांड एम्बेसडर, पोस्ट ऑफिस डिजाइन के सह–निमार्ता और सोशल मीडिया आउटरीच सहयोगी के रूप में शामिल कर रहा है।

देश में पहली बार, आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट फ्रैंचाइज मॉडल भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से छात्रों को डाक संचालन का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही छात्रों के लिए विशेष ब्रांडेड पार्सल पैकिंग की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि वे आसानी से पार्सल बुक कर सकें।

उद्घाटन समारोह में आईआईटी दिल्ली के निदेशक, डीन, फैकल्टी सदस्यों और छात्र संगठनों के योगदान की सराहना की गई , जिनकी रचनात्मक दृष्टि, सहभागिता और उत्साह से यह आधुनिक डाक घर को आकार मिल पाया है।

भारतीय डाक देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक, आकर्षक और सुलभ पोस्टल स्पेस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन और तकनीकी योगदान पर सहयोग के लिए आईआईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) ने दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन और तकनीकी योगदान पर सहयोग के लिए आईआईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

टीईसी और आईआईआईटी दिल्ली ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार साझेदारी को औपचारिक रूप दिया

समझौता का उद्देश्य स्वदेशी दूरसंचार तकनीक के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करना और ऊर्जा–कुशल दूरसंचार उपकरणों के लिए मानकों को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना है

(जीएनएस)।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) की तकनीकी शाखा दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन, अनुसंधान और तकनीकी योगदान पर सहयोग के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आईआईआईटी दिल्ली) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस साझेदारी का उद्देश्य भारत–विशिष्ट मानकों और परीक्षण ढांचे का विकास करना, दूरसंचार और संबंधित आईसीटी में सहयोगात्मक अनुसंधान, 6जी, ऑप्टिकल संचार, एनटीएन जैसे भविष्य के नेटवर्क प्रौद्योगिकियों का पता लगाना और राष्ट्रीय कार्य समूहों के माध्यम से आईटीयू–टी (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ–दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र) अध्ययन समूहों में भारत की भागीदारी को बढ़ाना है।

19 नवंबर 2025 को इस समझौता ज्ञापन पर टीईसी के डीडीजी (फिक्स्ड एक्सेस) श्री राकेश देसाई और

आईआईआईटी–दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉ. अभिजीत मित्रा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आईआईआईटी–दिल्ली के निदेशक डॉ. प्रो. रंजन बोस, टीईसी के डीडीजी (प्रशासन) श्री पवन गुप्ता और आईआईआईटी–डी के ईसीई विभाग के डॉ. प्रो. विवेक अशोक बोहरा उपस्थित थे।

इस साझेदारी के माध्यम से टीईसी के लिए अगली पीढ़ी के दूरसंचार और मानकीकरण गतिविधियों पर आईआईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर काम करने के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार हुआ है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

दूरसंचार में एआई: एआई–आधारित नेटवर्क अनुकूलन, विसंगति का पता लगाना, पूवार्नुमानित रखरखाव, कुशल यातायात प्रबंधन और दूरसंचार नेटवर्क में एआई–संचालित नीति प्रवर्तन

5जी/6जी: 5जी, 6जी, मिलीमीटर वेब, मल्टीपल–इनपुट मल्टीपल–आउटपुट, विषम नेटवर्क आदि के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और मानकीकरण गतिविधियां।

एसडीएन और एनएफवी: सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क (एसडीएन) और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन (एनएफवी) के क्षेत्र में संयुक्त अध्ययन और मानकीकरण गतिविधियां

मुक्त अंतरिक्ष ऑप्टिकल संचार/लाई–फाई : बैकहॉल और एक्सेस अनुप्रयोगों, विशेष रूप से ग्रामीण और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उच्च गति, कम विलंबता, विश्वसनीय, सुरक्षित, ऑप्टिकल वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन और तकनीकी योगदान।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां (आरईटी): दूरसंचार उपकरणों और बुनियादी ढांचे की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए आईसीटी का उपयोग।

इस साझेदारी का उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाना तथा आईटीयू और 3जीपीपी जैसे वैश्विक मानकीकरण निकायों में भारत के योगदान को मजबूत करके वैश्विक मानकीकरण प्रक्रियाओं में देश के वर्चस्व को बढ़ाना है।

यह सहयोग दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान, डिजाइन और विनिर्माण को मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। साथ ही इससे भारत–विशिष्ट मानकों, परीक्षण रूपरेखाओं और घरेलू समाधानों का भी विकास होगा जिससे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे को सुरक्षित कर आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।

टीईसी के बारे में

दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी), भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा है। यह भारत में दूरसंचार उपकरणों और नेटवर्क के लिए अंतर–संचालनीयता, गुणवत्ता और वैश्विक सर्वोत्तम विधियों के अनुरूप तकनीकी मानकों, विनिदेर्शों और अनुरूपता मूल्यांकन आवश्यकताओं को तैयार करता है। टीईसी, आईटीयू–टी, आईटीयू–आर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय कार्य समूहों का समन्वय करता है।

आईआईआईटी दिल्ली के बारे में

इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आईआईआईटी–दिल्ली) राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख संस्थान है जिसकी उन्नत दूरसंचार, 5जी/6जी प्रौद्योगिकियों, ऑप्टिकल संचार और उभरते हुए आईसीटी क्षेत्रों में सुदृढ़ शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमताएं हैं। आईआईआईटी–दिल्ली भारत में अग्रणी व्यापक अनुसंधान–आधारित शिक्षण संस्थानों में से एक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और समाज की उभरती जरूरतों के प्रति निरंतर संवेदनशील साबित हुआ है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

भाजपा यूपी-बंगाल में भी महिलाओं-युवाओं पर लगाएगी दांव

राजनीति के इस नए दौर में 'वाई' ही राज करेगा, जहां आधी आबादी और युवा ऊर्जा मिलकर इतिहास रचेंगे। कुल मिलाकर, बिहार की लहर अब पूरे हिदुस्तान को छू लेगी और भाजपा का यह दांव या तो मास्टरस्ट्रोक साबित होगा या सबक। वत्त ही बताएगा, लेकिन तैयारी तो जोरों पर है। भाजपा यूपी-बंगाल में भी महिलाओं-युवाओं पर लगाएगी दांव बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न सिर्प नीतीश वुमार को दसवीं बार मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, बल्कि भारतीय जनता पाटा को एक ऐसा फॉमूर्ला सौंप दिया जो अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में परखा जाएगा। एनडीए की 202 सीटों वाली ऐतिहासिक जीत के पीछे आधी आबादी का हाथ साफ दिख रहा है। महिलाओं ने 71.78 प्रतिशत मतदान कर पुरुषों के 62.98 प्रतिशत को पीछे छोड़ दिया, और यह आंकड़ा सिर्प संख्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक ांति का आईना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता इसे 'वाई' यानी वीमेन- यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स की जीत बता रहे हैं, जहां जातीय समीकरण टूटे और विकास की योजनाओं ने वोटों का ध्रुवीकरण किया। अब सवाल यह है कि क्या यह मॉडल यूपी की योगी सरकार और बंगाल की ममता बनजा की चुनौतियों को पार कर पाएगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हां, अगर बजट से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक सही दांव चले गए।बिहार की धरती पर जो वुछ हुआ, वह कोई संयोग नहीं था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, वुल 67.13 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 1951 के बाद का रिकॉर्ड है। लेकिन असली खेल तो महिलाओं ने खेला। नीतीश सरकार की 'महिला स्वरोजगार योजना' के तहत डेढ़ करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये की किस्त पहुंची, और यह पैसा वोटिग बूथों पर लंबीलंबी कतारों के रूप में दिखा। एक तरफ लालू प्रसाद के पुराने मुस्लिम-यादव (एमवाई) समीकरण की बातें हवा में तैर रही थीं, वहीं आधी आबादी ने एनडीए को ऐसा साथ दिया कि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। भाजपा अकेले 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पाटा बनी, और जनता दल यूनाइटेड को 85 मिलीं। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं ने न सिर्प संख्या बल्कि गुणवत्ता में भी योगदान दिया। जहां पुरुष वोटरों में सत्ता-विरोधी लहर की चर्चा थी, वहां महिलाओं ने योजनाओं के ठोस असर को प्राथमिकता दी। उदाहरण के तौर पर, दरभंगा की अलीनगर सीट से भाजपा की 25 वषाय लोक गायिका मैथिली ठावुर ने 11,730 वोटों से जीत हासिल की, जो युवा महिलाओं की नई ऊर्जा का प्रतीक बनीं। वुल 88 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनमें से 28 विजयी रहीं, और भाजपा ने 13 में से 10 को जीतकर रिकॉर्ड बनाया। यह जीत सिर्प सीटों की नहीं, बल्कि एक नए वोट बैंक की स्थापना की है, जहां जाति से ऊपर उठकर विकास और सुरक्षा का मुद्दा हावी हो गया।अब नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार साढ़े आठ साल के शासन में कानून-व्यवस्था का पर्याय बन चुकी है। बिहार की सफलता से प्रेरित होकर भाजपा यहां 'वाई' फॉमूर्ले को और मजबूत करने की तैयारी में है। फरवरी 2025 में पेश हुए 2025-26 के बजट को ही देख लीजिए 8,08,636 करोड़ रुपये का यह 'चुनावी बजट' महिलाओं और युवाओं पर वेंद्रित था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जो बेरोजगार युवाओं को लोन और ट्रेनिग का वादा करता है।इसी तरह, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना पर 2,980 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया, जिससे लाखों महिलाओं को मासिक सहायता मिलेगी। मेधावी छात्राओं को स्वूटी देने की योजना ने भी सरुखियां बटोरीं, और लाड़ली बहना जैसी योजनाओं की तर्ज पर महिलाओं को आर्थिक सशत्तिकरण का रोडमैप तैयार हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले बजट में रोजगार पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद पुलिस भता परीक्षा का आयोजन कर 60 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का तोहफा दिया, जो बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के हुआ।

भारत को मिलने वाली है यूएनएससी की वीटो पावर वाली स्थायी सीट, इस देश ने कर दिया समर्थन

(जीएनएस)।

80 साल बाद संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) के ढांचे में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है, और इस बार भारत के लिए स्थायी सदस्यता की राह आसान दिख रही है। बुधवार को वठरउ में 'रिफॉर्म' पर शुरू हुई बहस से मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि अगर सहमति बनती है, तो भारत को वीटो पावर के साथ यूएन की स्थायी सदस्यता मिल सकती है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में गठित यूएन का लक्ष्य दुनिया में शांति कायम करना था। वर्तमान में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस बार फ्रांस ने खुलकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, जो ब्रिटेन और रूस के बाद एक महत्वपूर्ण कदम है।

फ्रांस का सशक्त समर्थन: भारत के लिए गेम चेंजर

यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद (वठरउ) में सुधारों पर चल रही बहस के बीच, भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को फ्रांस का मजबूत समर्थन मिला है। ब्रिटेन और रूस लंबे समय से भारत का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब फ्रांस ने भी खुलकर वीटो पावर के साथ भारत को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की है। फ्रांस के दूत ने यूएनएससी रिफॉर्म की बैठक में अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती जिम्मेदारियों और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है। यह समर्थन भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यह भारत की दावेदारी को और मजबूत करता है।

चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन और जापान पर विरोध

वठरउ सुधारों पर चीन का रुख हमेशा से भारत के लिए एक चुनौती रहा है, लेकिन इस बार चीन ने भारत का सीधा विरोध नहीं किया है। चीन की स्थायी दूत ने बैठक में सिर्फ जी-4 के जापान का विरोध किया। चीन का तर्क है कि जापान जिस तरह से ताइवान के मुद्दे पर मुखर है, वह यूएन की स्थायी सदस्यता मांगने का अधिकार नहीं रखता। चीन ने जापान पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जापान को सदस्यता देने की कोशिश हुई तो वे इसका खुलकर विरोध करेंगे। चीन का

जापान पर केंद्रित विरोध भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत की राह में सीधे बाधा नहीं डाल रहा है।

आईजीएन प्रक्रिया का 17 साल बाद पुनरुद्धार

संयुक्त राष्ट्र में जान फूंकने और सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है, जो 17 साल बाद हो रहा है। इटली और पाकिस्तान जैसे देशों के विरोध के कारण यह प्रक्रिया पहले आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब यूएन ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया है और कुवैत के प्रतिनिधि को इसका नेतृत्व सौंपा गया है। इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य उन चार देशों की दावेदारी की जांच करना है जो स्थायी सदस्यता के लिए सक्षम माने जाते हैं (जी-4 देशों सहित)। यदि यह प्रक्रिया अपने अंतिम मुकाम तक पहुँचती है, तो भारत के लिए वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता प्राप्त करने की राह काफी आसान हो सकती है।

यूएन की स्थायी सदस्यता कैसे मिलती है?

यूएन की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए उसके चार्टर में संशोधन करना होता है, जिसके लिए अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 का उपयोग किया जाता है। किसी भी देश को स्थायी सदस्यता पाने के लिए दो प्रमुख मोर्चों पर समर्थन प्राप्त करना होता है। पहला, अनुच्छेद 109 के तहत उसे वर्तमान के सभी पांच स्थायी सदस्यों (चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस) का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी देश वीटो नहीं करता है, तो संबंधित देश योग्य माना जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 108 के तहत स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव यूएन जनरल असेंबली में रखा जाता है, जहाँ 193 सदस्य देशों में से दो-तिहाई (यानी 145 देशों) का समर्थन अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 को संबोधित किया

प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपये की 21वीं पीएम-किसान किस्त जारी की

भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक केन्द्र बनने की राह पर है: प्रधानमंत्री

भारत के युवा खेती को एक मॉडर्न और बड़े पैमाने पर बढ़ने वाले मौके के तौर पर तेजी से पहचान रहे हैं; इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी: प्रधानमंत्री

प्राकृतिक खेती भारत की अपनी देसी अवधारणा है; यह हमारी परंपराओं में बसा है और हमारे पर्यावरण के लिए सटीक है: प्रधानमंत्री

ह्यएक एकड़, एक सीजन'- एक एकड़ जमीन पर एक सीजन के लिए प्राकृतिक खेती करें: प्रधानमंत्री

हमारा लक्ष्य प्राकृतिक खेती को पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित आंदोलन बनाना हो: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, श्री मोदी ने कोयंबटूर की पवित्र धरती पर मरुधमलाई के भगवान मुरुगन को नमन करके अपनी बात शुरू की। उन्होंने कोयंबटूर को संस्कृति, दया और रचनात्मकता की धरती बताया और इसे दक्षिण भारत की उद्यमिता का शक्ति केन्द्र के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहर का वस्त्र सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोयंबटूर ने अब और नाम कमाया है, क्योंकि इसके पूर्व सांसद श्री सी.पी. राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति के तौर पर देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

यह बताते हुए कि प्राकृतिक खेती उनके दिल के बहुत करीब का विषय

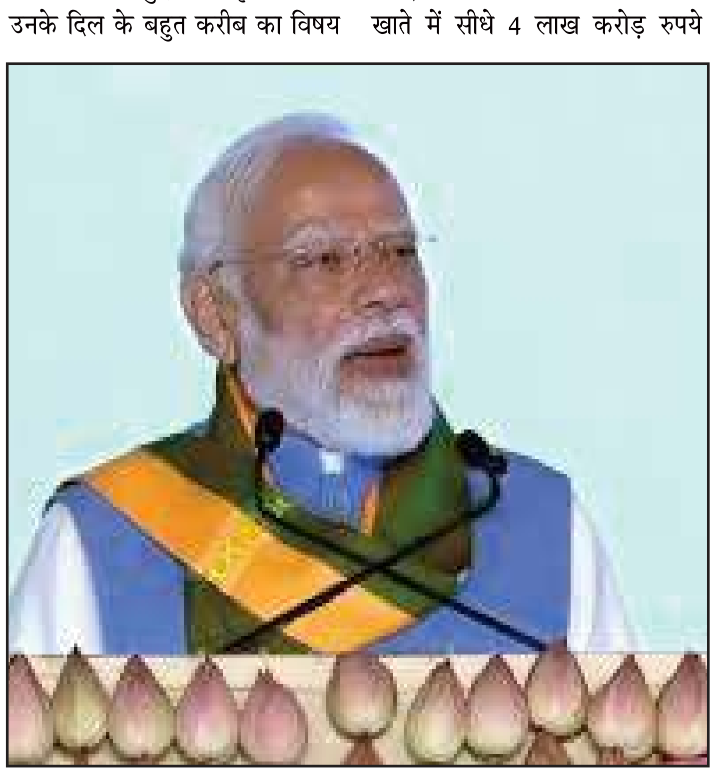

है, श्री मोदी ने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट के आयोजन के लिए तमिलनाडु के सभी किसान भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के साझेदारों, स्टार्टअप उद्यमों और नवाचार के सूत्रधारों की मौजूदगी को स्वीकार किया और सभी प्रतिभागियों को दिल से बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में, वे भारतीय खेती में बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, 'भारत प्राकृतिक खेती का ग्लोबल हब बनने की राह पर है ह्व उन्होंने कहा कि देश की जैव-विविधता बदल रही है और युवा अब खेती को एक आधुनिक, बड़े पैमाने पर बढ़ने वाले अवसर के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती देगा।

पिछले ग्यारह सालों में पूरे कृषि क्षेत्र में हुए बड़े बदलावों पर जोर देते हुए, श्री मोदी ने बताया कि भारत का कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है और सरकार ने कृषि को मॉडर्न बनाने में किसानों की मदद के लिए हर मुमकिन रास्ता खोला है। यह बताते हुए कि अकेले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम के जरिए, इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि सात साल पहले जब से पशुधन और मछली पालन सेक्टर को केसीसी का फायदा दिया गया है, तब से इन एरिया में काम करने वाले लोग भी इसका बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जैविक खाद पर जीएसटी में कमी लाने से किसानों को और भी अधिक लाभ हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देर पहले ही, इसी मंच से, प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई, जिससे देश भर के किसानों को 18,000 करोड़ रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए गए। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि तमिलनाडु के लाखों किसानों को भी उनके खाते में पैसे मिल गए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस स्कीम के तहत, अब तक छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे 4 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जिससे वे खेती-बाड़ी की अपनी अलग-अलग जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। उन्होंने इस पहल से फायदा उठाने वाले करोड़ों किसानों को शुभकामनाएं दीं।

21वीं सदी की खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ाने पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में, बढ़ती मांग की वजह से खेतों और खेती से जुड़े अलग-अलग सेक्टर में केमिकल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, मिट्टी की नमी पर असर पड़ रहा है और हर साल खेती की लागत बढ़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका हल फसल विविधता और प्राकृतिक खेती में है।

मिट्टी की उर्वरा शक्ति को फिर से बढ़ाने और फसलों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को प्राकृतिक खेती के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि यह एक विजन और जरूरत दोनों है। तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जैव-विविधता को बचाकर रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक खेती हमें जलवायु परिवर्तन और मौसम के उतार-चढ़ाव का सामना करने में मदद करती है, हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखती है और लोगों को नुकसानदायक रसायनों से बचाती है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन इस जरूरी मिशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है, श्री मोदी ने बताया कि एक साल पहले, केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था, जिससे लाखों किसान पहले ही जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल का अच्छा असर खासकर दक्षिण भारत में दिख रहा है। अकेले तमिलनाडु में लगभग 35,000 हेक्टेयर जमीन पर अब जैविक और प्राकृतिक खेती हो रही है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, 'प्राकृतिक खेती भारत की एक देसी अवधारणा है, यह कहीं और से आयातिक नहीं है, बल्कि यह परंपरा से पैदा हुई है और पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है ह्व उन्होंने खुशी जताई कि दक्षिण भारत के किसान लगातार पारंपरिक प्राकृतिक खेती के तरीके जैसे पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तरीकों से मिट्टी की सेहत बेहतर होती है, फसलें रसायनों से मुक्त रहती हैं और फसल की लागत कम होती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अन्न यानी बाजरा की खेती को प्राकृतिक खेती के साथ मिलाना धरती मां की रक्षा करने में बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को थेनम थिनाई मावुम चढ़ाया जाता है, जो शहद और श्री अन्न से बनता है। उन्होंने बताया कि तमिल इलाकों में कंबू और समाई जैसे बाजरे, केरल और कर्नाटक में रागी और तेलुगु बोलने वाले राज्यों में सजा और जोन्ना पीढ़ियों से पारंपरिक आहार का हिस्सा रहे हैं।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार इस सुपरफूड को वैश्विक बाजार तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक और रसायन-मुक्त खेती उनकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस समिट में ऐसी कोशिशों पर चर्चा होनी चाहिए।

एक ही फसल की खेती के बजाय फसल विविधता जैसी खेती को बढ़ावा देने की अपनी लगातार अपील को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने माना कि दक्षिण भारत के कई इलाके इस मामले में प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उन्होंने बताया कि केरल और कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में सीढीनुमा खेती के उदाहरण साफ तौर पर दिखाई देते हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक ही खेत में नारियल, सुपारी और फलों के पौधे उगाए जाते हैं और नीचे मसाले तथा काली मिर्च उगाई जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छोटे प्लॉट पर इस तरह की समन्वित खेती प्राकृतिक खेती की मूल सोच को दशार्ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती के इस मॉडल को पूरे भारत में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से इस बात पर विचार करने की अपील करते हुए कहा कि इन तरीकों को देश के अलग-अलग इलाकों में कैसे लागू किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण भारत खेती की जीती-जागती यूनिवर्सिटी रहा है। उन्होंने बताया कि यह इलाका दुनिया के कुछ सबसे पुराने चालू डैम का घर है और कलिंगारायण नहर 13वीं सदी में यहीं बनी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस इलाके के मंदिरों के तालाब विकेन्द्रित जल संरक्षण प्रणाली के मॉडल बन गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जमीन ने हजारों साल पहले खेती के लिए नदी के पानी को रेगुलेट करके वैज्ञानिक तौर पर जल संबंधी इंजीनियरी की शुरूआत की थी। उन्होंने भरोसा जताया कि देश और दुनिया के लिए प्राकृतिक खेती को लेकर नेतृत्व भी इसी इलाके से आएगी।

इस बात पर जोर देते हुए कि एक विकसित भारत के लिए भविष्योन्मुखी कृषि प्रणाली बनाने के लिए मिलकर कोशिश करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री ने किसानों से 'एक एकड़, एक सीजनह्व प्राकृतिक खेती शुरू करने और उसे करने एवं उसके परिणाम के आधार पर आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों से प्राकृतिक खेती को कृषि के पाठ्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा बनाने की अपील की और उन्हें किसानों के खेतों को जीती-जागती लैब की तरह इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारा लक्ष्य प्राकृतिक खेती को पूरी तरह से विज्ञान आधारित आंदोलन बनाना हो ह्व

श्री मोदी ने इस अभियान में राज्य सरकारों और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की अहम भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में 10,000 एफपीओ बनाए गए हैं। उनके समर्थन से, छोटे किसान क्लस्टर बनाए जा सकते हैं, जिन्हें सफाई, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की सुविधाओं से लैस किया जा सकता है, और सीधे ई-नाम जैसे ऑनलाइन मार्केट से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक ताकत और सरकारी मदद एक साथ आएंगे, तो किसान तरक्की करेंगे और धरती मां स्वस्थ रहेंगी।

प्रधानमंत्री ने यह विश्वास जताते हुए अपनी बात खत्म की कि यह समिट देश में प्राकृतिक खेती को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि इस मंच से नई अवधारणा और नए समाधान निकलेंगे।

इस आयोजन में तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि, केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

तमिलनाडु नेचुरल फार्मिंग स्टेकहोल्डर्स फोरम द्वारा आयोजित साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 19 से 21 नवंबर, 2025 तक चलेगा। इस समिट का मकसद सतत, पर्यावरण-अनुकूल और रसायन-मुक्त खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है और भारत के खेती के भविष्य के लिए एक सटीक, जलवायु-अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल के तौर पर प्राकृतिक और उर्वरा शक्ति की पुनर्प्राप्ति वाली खेती की ओर तेजी से बदलाव लाना है।

समिट में किसान-उत्पादक संगठन और ग्रामीण उद्यम के लिए बाजार संपर्क जबनाने पर भी फोकस किया जाएगा, साथ ही जैविक खाद के इस्तेमाल, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, जलवायु-अनुकूल पैकेजिंग और देसी प्रौद्योगिकी में नवाचार दिखाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 50,000 से अधिक किसान, प्राकृतिक खेती करने वाले, वैज्ञानिक, जैविक खाद के आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक हिस्सा लेंगे।

नई दिल्ली में क्षेत्रीय ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 का आयोजन

वैश्विक स्वास्थ्य के लिए इंटरऑपरेबिलिटी और जेन एआई को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में क्षेत्रीय ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 का आयोजन

शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण में स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलाव के लिए सुदृढ़ सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने समावेशी, अंतर-संचालनीय और नागरिक-केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया

एनएचए के सीईओ डॉ. सुनील कुमार बरनवाल ने जेन एआई को जिम्मेदारी से अपनाने और डेटा गुणवत्ता और अंतर-संचालनीयता की केंद्रीयता पर प्रकाश डाला

प्रविष्टि तिथिः 19 ठडश 2025 6:03ढट ु८ ढक्ह ऊँ

क्षेत्रीय ओपन डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 (19-20 नवंबर 2025) का आज यहां उद्घाटन किया गया, जिसमें डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (एसईएआर) के नीति निमार्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों, सार्वजनिक स्वास्थ्य नेताओं और वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डब्ल्यूएचओ-एसईएआरओ और यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में खुले, अंतर-संचालनीय और मानक-आधारित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाना है।

उद्घाटन भाषण देते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्यसलिला श्रीवास्तव ने कहा कि इस क्षेत्र के देश भूगोल, क्षमता और पैमाने में भिन्न होने के बावजूद, पहुँच, सामर्थ्य, कार्यबल की कमी और बुनियादी ढाँचे की कमियों जैसी समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा,

"अलग-अलग देखने पर ये चुनौतियाँ अलग-अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन इनमें एक समानता है – हमारे क्षेत्र को ऐसी एकीकृत, नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकता है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए पहुँच और समानता के अंतर को पाट सकें।"

उन्होंने मजबूत शासन, खुले मानकों और उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपने डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में भारत की यात्रा को रेखांकित किया। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट (2019) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि "भारत का डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र अंतर-संचालनीयता, डिजाइन द्वारा गोपनीयता और नागरिक-केंद्रिकता पर आधारित है, और इसकी आधारभूत संरचना में जेनएआई का जिम्मेदारी से उपयोग शामिल है।"

स्वास्थ्य के लिए जेनएआई के उपयोग में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, "पूरे देश में, एआई-सक्षम निगरानी और निदान हमें बीमारियों की तेजी से पहचान करने, प्रकोप का पहले से अनुमान लगाने और देश के सबसे दूरदराज इलाकों के अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समर्थन करने में मदद कर रहे हैं।" उन्होंने आईडीएसपी के तहत एआई-संचालित रोग निगरानी, टीबी के लिए जोखिम पूवार्नुमान, भेद्यता मानचित्रण, और मधुमेह रेटिनोपैथी, मौखिक कैंसर और त्वचा रोगों जैसी स्थितियों के लिए एआई-आधारित स्क्रीनिंग मॉडल सहित ठोस उदाहरणों का हवाला दिया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के स्वास्थ्य कार्यबल को भी जेनएआई द्वारा संचालित निर्णय-समर्थन उपकरणों का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, "डॉक्टर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के मुख्य हितधारक हैं। ई-संजीवनी के साथ एकीकृत क्लिनिकल निर्णय सहायता प्रणाली ने दो लाख से ज्यादा डॉक्टरों को सहयोग दिया है और बीस करोड़ से ज्यादा मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुँच में सुधार किया है।" उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी इसी तरह के उपकरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे हम इन उपकरणों का विस्तार कर रहे हैं, हम इस बात पर स्पष्ट हैं कि एआई पारदर्शी, साक्ष्य-आधारित होना चाहिए और कभी भी एक अपारदर्शी ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए।"

सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करते हुए, श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा, "डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, खुले मानक और ज़िम्मेदार जेनएआई अब वैकल्पिक संसाधन नहीं रह गए हैं – ये सुदृढ़ और भविष्य की स्वास्थ्य प्रणालियों के आधारभूत स्तंभ हैं।" उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन देशों को सीख साझा करने, दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करने और डिजिटल स्वास्थ्य को एक क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तु के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉ. सुनील कुमार बरनवाल ने जनरेटिव एआई के ज़िम्मेदार, प्रासंगिक और साक्ष्य-आधारित उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जनरेटिव एआई क्लीनिकल विशेषज्ञता का विकल्प नहीं है – यह मानवीय क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन इसका प्रभाव डेटा की गुणवत्ता और अंतर-संचालनीयता से सीधे जुड़े हैं।"

"डिजिटल स्वास्थ्य अंतरसंचालनीयता में उभरती प्रथाएँ – वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जेन एआई" विषय पर मुख्य भाषण देते हुए, उन्होंने क्षेत्र में असमान रूप से बढ़ते रोग भार, स्वास्थ्य कार्यबल की कमी और लगातार संरचनात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खुले मानक, खुली प्रौद्योगिकियाँ, खुली वास्तुकलाएँ और खुली विषय-वस्तु – पूर्ण-एसटीसीए दृष्टिकोण – ज़िम्मेदार एआई परिनियोजन के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं।

उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ऐबीडीएम) और पीएम-जय के तहत भारत के अनुभवों को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे एकीकृत स्वास्थ्य पहचानकर्ता (एबीएचए), रजिस्ट्रियाँ, सहमति ढाँचे और डिजिटल वर्कफ़्लो उन्नत एआई के बड़े पैमाने पर उपयोग से पहले आवश्यक आधारभूत ढाँचा तैयार करते हैं।

महापौर, नगर आयुक्त ने राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त कर मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात, सीएम ने दिया विशेष संदेश

गोरखपुर ने जल संचयन, प्राकृतिक जल शोधन और तालाबों-नालों के पुनर्जीवन को जिस रूप में जन आंदोलन बनाया है, वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। 'गोरखपुर मॉडल' अब अन्य नगरों के लिए भी आदर्श बनेगा।

(जीएनएस)।

गोरखपुर नगर निगम ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025' समारोह में गोरखपुर को जल संचय जन भागीदारी अभियान (खरखइ 1.0) के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान और उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने यह सम्मान गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल को प्रदान किया।

सीएम ने नगर निगम टीम को दी बधाई

सम्मान प्राप्त करने के बाद दोनों अधिकारियों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की और उन्हें शहर की इस उपलब्धि की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने नगर निगम टीम को हार्दिक बधाई देते हुए गोरखपुरवासियों के लिए विशेष संदेश भी जारी किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर वासियों के लिए संदेश

गोरखपुर ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि जब जनता और प्रशासन एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी सरल हो जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करना गोरखपुर नगर की सामूहिक चेतना, जन भागीदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का उज्ज्वल उदाहरण है। मैं गोरखपुर की जनता, नगर निगम टीम और सभी सहयोगी संस्थाओं को इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हृदय से शुभकामनाएँ देता हूँ।

'गोरखपुर मॉडल' अब अन्य नगरों के लिए भी आदर्श बनेगा

जल संरक्षण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मैं गोरखपुर के नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसी उत्साह के साथ शहर को जल-सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करते रहें। मिलकर हम अपने शहर को सतत विकास की दिशा में देश का अग्रणी नगर बनाएँगे। गोरखपुर के जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत—वर्षा जल संचयन संरचनाओं का विस्तार, तालाबों और कुओं की सफाई, नदियों और नालों के पुनर्जीवन, तथा तकिया घाट पर स्थापित नेचुरल वॉटर फिल्ट्रेशन सिस्टम जैसी नवाचारी पहलें राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से सराही गईं। तकिया घाट का प्राकृतिक जल शोधन केंद्र बिना रसायन उपयोग के नदी के प्रदूषित जल को शुद्ध करने का अनोखा मॉडल है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।

पीलीभीत: सपा नेता ओमप्रकाश मिश्रा का आकस्मिक निधन - मुड़िया हुलास में शोक की लहर, कार्यकताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित!

- मुलायम सिंह के आंदोलनों में सक्रिय, बूथ से जिला स्तर तक योगदान; हरिपाल सिंह समेत नेताओं ने प्रार्थना की

(जीएनएस)।

पीलीभीत/बीसलपुर।समाजवादी पार्टी पीलीभीत के वरिष्ठ नेता श्री ओमप्रकाश मिश्रा निवासी ग्राम मुड़िया हुलास, थाना बरखेड़ा कलां, तहसील बीसलपुर का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।

ओमप्रकाश मिश्रा जी समाजवादी विचारधारा के सच्चे समर्थक रहे। समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक वे पार्टी की नीतियों और मूल्यों के प्रति समर्पित रहे। नेताजी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्वकाल में उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया और कई बार जेल भी गए।

पार्टी में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

निधन की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के नेता हरिपाल सिंह लोधी, राम प्रताप गंगवार, विनोद दिवाकर, शैलेश शर्मा एडवोकेट, विवेक गंगवार, लाजपत गंगवार, ओमपाल गंगवार, जगदीश कुमार वर्मा, मीनाक्षी गंगवार, गुलजारी लाल वर्मा सहित तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

शारदा नदी किनारे बकरे की कुबार्नी का प्रयास।

(जीएनएस)।

पीलीभीत पूरनपुर।धनारा घाट: शारदा नदी किनारे बकरे की कुबार्नी का प्रयास, गौ रक्षक अनिकेत व प्रिंस ने वीडियो बनाया तो इको गाड़ी से आए आरोपी बकरा उठाकर भागे झ ठाकुर शिवम सिंह भदोरिया ने पुलिस से शिकायत शिकायत की है। सनातन भावनाओं को ठेस, हिंदू संगठनों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग।

दिनांक 19 नवंबर को पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील में स्थित धनारा घाट पर दोपहर एक ऐसी घटना घटी, जिसने सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई। पवित्र शारदा नदी के तट पर, जहां भक्त शांति से पूजा-अर्चना करते हैं, वहां कुछ संदिग्ध लोग इको गाड़ी से पहुंचकर नहर किनारे बकरा काटने की कोशिश करने लगे। जन्मदिन के अवसर पर शारदा मैया के दर्शन के लिए गए गौ रक्षक अनिकेत व प्रिंस ने इस हरकत को देखा और तुरंत वीडियो बनाकर विरोध जताया। आरोपी जल्दबाजी में बकरा उठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गौ सेवा टीम पूरनपुर के प्रमुख ठाकुर शिवम सिंह भदोरिया ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों में गुस्सा भड़क गया है, और ठाकुर शिवम सिंह भदोरिया ने चेतावनी दी कि आरोपी न पकड़े गए तो आंदोलन छेड़ा जाएगा।यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे धनारा घाट पर घटी। ठाकुर शिवम सिंह भदोरिया की गौ सेवा टीम से जुड़े युवा गौ रक्षक अनिकेत व प्रिंस अपना जन्मदिन मनाने गए थे। वे शारदा मैया के दर्शन के लिए पवित्र तट पर पहुंचे, जहां नदी का स्वच्छ जल और शांत वातावरण भक्तों को आकर्षित करता है। लेकिन वहां का नजारा देखकर वे स्तब्ध रह गए। इको गाड़ी से उतरे 4-5 संदिग्ध व्यक्ति नदी के किनारे बकरे को बांधे हुए थे और काट रहे थे।गौ रक्षकों ने तुरंत मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया और आरोपी से पूछताछ की। इतना देखते ही संदिग्ध घबरा गए। उन्होंने अधूरा बकरा उठाया और इको गाड़ी में सवार होकर मौके से भाग निकले। अनिकेत ने बताया, "हम पूजा करने आए थे, लेकिन ये लोग मां शारदा के तट को अपवित्र करने पर तुले थे। वीडियो में सब साफ दिख रहा। हमने तुरंत ठाकुर शिवम सिंह भदोरिया को सूचना दी।

महाराष्ट्र: बकाया बिजली बिल से राहत! सरकार का बड़ा 'पावर बूस्टर' तैयार, कैसे होगा लोगों को फायदा?

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार (19 नवंबर 2025) को महावितरण (टरएऊछ) को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने केंद्र के लेट पेमेंट सरचार्ज (छढर) नियमों के तहत बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों का लंबित बकाया चुकाने के लिए 5,252.28 करोड़ रुपये के लोन की स्टेट गारंटी को मंजूरी दे दी। यह राशि हुडको और यूको बैंक से जुटाई जाएगी।

कितना लोन, कहां से और कितनी ब्याज दर?

हुडको से: ₹2,785.37 करोड़ @ 8.95% सालाना

यूको बैंक से: ₹2,466.90 करोड़ @ 8.45% सालाना

कुल: ₹5,252.28 करोड़ (मूलधन ₹3,653.25 करोड़ + ब्याज ₹1,899.02 करोड़)

यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 की मासिक किश्तों के लिए इस्तेमाल होगी।

कुल बकाया कितना?

महावितरण पर बिजली उत्पादकों और ट्रांसमिशन कंपनियों का कुल बकाया करीब ₹17,252 करोड़ है। इसमें ब्याज जोड़कर राशि ₹29,230 करोड़ तक पहुंचती है। सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक पांच साल में इस बकाया को चुकाने का प्लान बनाया है।

अब तक कितनी गारंटी दी?

पहले चरण: ₹13,552.12 करोड़

दूसरे चरण: ₹7,619.69 करोड़

तीसरा चरण (बुधवार): ₹5,252.28 करोड़

कुल गारंटी अब तक: करीब ₹26,424 करोड़

सख्त शर्तें भी लगाईं

सरकार ने साफ किया है:

गारंटी सिर्फ ₹5,252.28 करोड़ तक सीमित रहेगी। देरी से पेमेंट पर पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कवर होगा।

महावितरण को लोन देने वाली संस्थाओं को पर्याप्त सिक्योरिटी (कोलेटरल) देनी होगी।

हर 6 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊर्जा विभाग को जमा करना होगा।

लोन का दुरुपयोग या सिक्योरिटी न देने पर गारंटी अपने आप रद्द हो जाएगी।

कैबिनेट ने इस बार गारंटी फीस भी माफ कर दी है।

क्यों जरूरी थी यह गारंटी?

छढर नियमों के तहत अगर डिस्कॉम समय पर बकाया नहीं चुकाते तो बिजली सप्लाई कट सकती है। महावितरण पहले से ही भारी कर्ज में है। स्टेट गारंटी मिलने से उसे कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा और बिजली उत्पादकों का भरोसा कायम रहेगा। इससे राज्य में बिजली आपूर्ति सुचारु बनी रहेगी।

ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह कदम वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के साथ-साथ बिजली क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी था।' महाराष्ट्र इस साल अब तक महावितरण के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपये की गारंटी दे चुका है। अगले दो साल में भी इसी तरह की गारंटी की जरूरत पड़ सकती है।

निरीक्षण पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एक मिनी बस में सभी अधिकारियों ने साथ बैठकर किया।

प्रयागराज (जीएनएस)।

इसमें अपर पुलिस महानिदेशक डॉ॰ संजीव गुप्ता, मण्डलायुक्त श्रीमती सौम्या अग्रवाल, आइजी प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्रा, पुलिस आयुक्त प्रयागराज श्री जोगिंदर कुमार, एडिशनल कमिश्नर पुलिस डॉ अजय पाल, जिलाधिकारी श्री मनीष वर्मा, मेला अधिकारी श्री ऋषिराज, नगरायुक्त श्री सीलम साई तेजा, अपर मेला अधिकारी श्री दयानंद प्रसाद, उप मेलाधिकारी विवेक शुक्ला समेत सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे।

खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, प्रयागराज एवं जिला प्रशासन, प्रयागराज द्वारा दिनांक 19-11-2025 को प्रयागराज में 40वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इन्दिरा मैराथन का आयोजन किया गया।

प्रयागराज (जीएनएस)।

मैराथन का शुभारम्भ आनन्द भवन, प्रयागराज से प्रातः 6.30 बजे श्रीमती सौम्या अग्रवाल, (आई०ए०एस०) आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज एवं जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा द्वारा एवं समापन तथा पुरस्कार वितरण डा० आर०पी० सिंह निदेशक, खेल उ०प्र०, लखनऊ के कर कमलों द्वारा मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, प्रयागराज में किया गया। इस अवसर पर श्री विनोद कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज, श्री श्याम बाबू गुप्ता वरिष्ठ खिलाड़ी श्री अभिन्न श्याम गुप्ता, अर्जुन एवार्डी, श्री प्रमोद तिवारी, लक्ष्मण एवार्डी, श्री चन्द्रोदय नारायण सिंह, लक्ष्मण एवार्डी एवं श्री जितेन्द्र यादव, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी मेरठ, श्री आले हैदर, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी गोरखपुर, श्री अनिमेष सक्सेना, क्षेत्रीय कीडाधिकारी अयोध्या, श्रीमती विमला सिंह, क्षेत्रीय कीड़ा अधिकारी वाराणसी, श्री सुनील कुमार भारती, कीड़ाधिकारी, फतेहपुर, श्री अरविन्द कुमार सोनकर, कीड़ाधिकारी, चित्रकूट, श्री राहुल चोपडा, क्रीड़ाधिकारी, सहानपुर, श्री रूस्तम खॉन, मैराथन प्रवेक्षक, सुश्री पूनमलताराज, कीडाधिकारी प्रतापगढ़ तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर जगत तारण गर्ल्स इन्टर कालेज, प्रयागराज की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मन्दिर गंगापुरी, प्रयागराज, ज्वाला देवी बालिका इण्टर कालेज, ममफोर्डगंज, प्रयागराज एवं आर्य कन्या इन्टर कालेज, प्रयागराज की बालिकाओं द्वारा नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 40वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इन्दिरा मैराथन के पुरूष एवं महिला वर्ग के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:-

महिला वर्ग

प्रथम स्थान : सुश्री रीतू ।

द्वितीय स्थान : सुश्री अश्विनी मदन जाधव।

तृतीय स्थान:सुश्री ज्योति शंकर गवते।

पुरुष वर्ग

प्रथम स्थान:प्रदीप सिंह चौधरी

द्वितीय स्थान:ज्ञान बाबू

तृतीय स्थान:रोहित सरोज

कमरे में फांसी लगाकर मोची ने की आत्महत्या पंचायत सदस्य की मानसिक स्थिति नहीं थी ठीक, पुलिस ने शुरू की जांच

मलिहाबाद। नई बस्ती धनेवा गांव में मोची का काम करने वाले एक युवक ने बुधवार सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान भगवानदीन (35) के रूप में हुई है, जो अपनी ग्रामसभा में पंचायत सदस्य भी थे।

पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।परिजनों के अनुसार, मृतक भगवानदीन की मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं बताई जा रही थी और वह उपचाराधीन भी थे। बुधवार सुबह वह अपने घर में लिंटर के पावे (पिलर) में रस्सी के सहारे लटकते हुए मिले।

परिजनों द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद, उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुँचे।भगवानदीन के परिवार में उनकी पत्नी निशा के अलावा दो भाई और तीन बहनें हैं, जो सभी विवाहित हैं। इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है।

पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आत्महत्या के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

भोपाल में दलित-पिछड़ा गुस्सा: सिविल जज भर्ती में रिजर्वेशन के 148 पद खाली, डीपीएसएस ने घेरा मंत्री का बंगला

(जीएनएस)।

भाई साहब... ये कैसी भर्ती हो रही है मध्य प्रदेश में? 121 अनुसूचित जनजाति के पद... एक भी चयन नहीं। 18 अनुसूचित जाति के पद... सिर्फ एक चयन। 9 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद... सिर्फ 5 चयन। और सरकार खामोश... हाई कोर्ट की चयन समिति मौन... और आरक्षित वर्ग का गुस्सा आसमान छू रहा है।"

ये शब्द आज भोपाल की सड़कों पर गूंज रहे थे। दलित पिछड़ा समाज संगठन (DPSS) के सैकड़ों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2022 सिविल जज भर्ती में आरक्षित वर्ग के साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरे।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकताओं ने पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और फिर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के शासकीय आवास का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने तरण पुष्कर चौराहे पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, लेकिन संदेश साफ था - "जब तक न्याय नहीं, चैन नहीं।"

विवाद का सार: क्या है समस्या?

भर्ती का पैमाना: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 2022 में अधिसूचित सिविल जज भर्ती के तहत कुल 191 पद थे। इनमें आरक्षित वर्गों के लिए 148 पद (रळ: 121, रउ: 18, डइउ: 9) निर्धारित थे।

चयन परिणाम: अंतिम चयन में केवल 47 अभ्यर्थी ही सफल हुए। आरक्षित वर्गों में चयन बेहद निराशाजनक रहा:

ST (121 पद): 0 चयन।

SC (18 पद): 1 चयन।

OBC (9 पद): 5 चयन।

आरोप: DPSS और अन्य संगठनों का कहना है कि यह "आरक्षण घोटाला" है। खाली पदों को भरने के बजाय उन्हें रिक्त छोड़ दिया गया, जो संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों (अनुच्छेद 16(4), 335) का उल्लंघन है। दामोदर सिंह यादव ने इसे "सामाजिक न्याय पर प्रहार" बताते हुए परीक्षा निरस्त करने और पारदर्शी पुनः परीक्षा की मांग की है। उन्होंने वढरउ जैसी केंद्रीय परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के सफल होने का हवाला देते हुए टढढरउ/टढलउ की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कुल मिलाकर आरक्षित वर्ग के 148 पदों में सिर्फ 6 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। बाकी 142 पद खाली रह गए।

"ये गलती नहीं, डिजाइन है" - दामोदर सिंह यादव

प्रदर्शन के दौरान दामोदर सिंह यादव ने कहा, "कहते हैं न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की इस भर्ती में तो लगता है कि पट्टी के पीछे भी कुछ और चल रहा था। ये कोई गलती नहीं, ये एक सोचा-समझा डिजाइन है। न्यायपालिका में आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने का प्रयोग चल रहा है।"

उन्होंने तीखा सवाल उठाया - "UPSC जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में SC, ST, OBC के बच्चे टॉप करते हैं। वहाँ मेरिट बन जाती है, यहाँ मध्य प्रदेश की सिविल जज भर्ती में 148 पद खाली कैसे रह गए? क्या हमारे बच्चे अचानक कमजोर हो गए?"

दोनों बड़ी पार्टियों पर हमला: "BJP हो या कांग्रेस, दोनों आरक्षण विरोधी"

दामोदर यादव ने सत्ताधारी भाजपा के साथ-साथ विपक्षी कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। "हमने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा (भाजपा) और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (कांग्रेस) दोनों के घर का घेराव किया, क्योंकि दोनों ही रउ, रळ, डइउ के हक मारने में एक जैसे हैं। एक सत्ता में है, दूसरा सत्ता की राह देख रहा है - दोनों आरक्षण विरोधी हैं।"

सुबह से ही DPSS कार्यकर्ता भोपाल के अलग-अलग इलाकों से एकत्र होने लगे थे। हाथों में तख्तियां थीं -

"आरक्षण हमारा हक है, कोई समझौता नहीं" "148 पद खाली = सामाजिक न्याय की हत्या" "परीक्षा रद्द करो, पुनः परीक्षा कराओ"

पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तरण पुष्कर चौराहे पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। लेकिन कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और नारे लगाते रहे। दामोदर यादव ने ऐलान किया, "आज हम सैकड़ों में थे, अगली बार हजारों में आएंगे। जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, आंदोलन नहीं रुकेगा।"

मामला कोर्ट में भी गर्म

इधर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी इस भर्ती को लेकर ढक्छ दाखिल हो चुकी है। याचिकाकताओं का कहना है कि मेरिट लिस्ट बनाने में मनमानी हुई और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जानबूझकर कम अंक दिए गए। हाई कोर्ट ने फिलहाल सभी नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है।

आखिरी सवाल वही - क्या वाकई न्याय अंधा है?

आज भोपाल की सड़कों पर जो गुस्सा दिखा, वह सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का नहीं है। यह उस पूरे सिस्टम का गुस्सा है, जिसमें संवैधानिक आरक्षण को बार-बार कागजों तक सीमित करने की कोशिश की जाती है।

दामोदर सिंह यादव ने अंत में कहा, "हम लड़ रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जज बनें, वकील बनें, अफसर बनें। हम लड़ रहे हैं ताकि न्याय की देवी की पट्टी हटे... और वह सचमुच अंधी न रह जाए।"

आंदोलन जारी है। अगला कदम क्या होगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में आरक्षित वर्ग की आवाज आज और बुलंद हो गई है।

फ्लॉप फिल्मों के बाद भी सलमान खान नहीं ले रहे सबक, 'बैटल ऑफ गलवान' में भी दोहरा गलतियां!

(जीएनएस)।

'सिकंदर' की असफलता के बाद सलमान खान अपने काम करने के तरीकों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन सलमान ने अपनी वर्किंग स्टाइल में बदलाव करने के बजाय इसे लेकर और स्पष्ट रुख अपनाया है। नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के निर्देशक अपूर्व लाखिया से शूटिंग टाइमिंग पर खुलकर बात की है।

'सिकंदर' के फ्लॉप होने के बाद निर्देशक ए. आर. मुरुगादोस ने यह दावा किया था कि सलमान के देर से सेट पर पहुंचने की आदत फिल्म की नाकामी का एक बड़ा कारण रही। यह बयान सामने आने के बाद सलमान खान और उनके कार्यशैली को लेकर बहस तेज हो गई। इसी पृष्ठभूमि में सलमान ने अपूर्व लाखिया से मुलाकात की और अपने समय-सारणी को लेकर स्पष्टता दी।

वर्क रिदम नहीं बदल सकता

एक सूत्र के मुताबिक सलमान ने निर्देशक से कहा, "देखो भाई, मैं अपना वर्क रिदम नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें रोज शूट पर आने का अपना सही समय पहले ही बता दूंगा। अगर मैंने कहा कि मैं शाम 6 बजे आऊंगा, तो मैं ठीक 6 बजे पहुंच जाऊंगा। ऐसे में अगर आप सुबह 9 बजे पूरी टीम बुला लें, तो वो आपकी गलती होगी।" सलमान के इस बयान के बाद निर्देशक अपूर्व लाखिया ने पूरी शूटिंग का शेड्यूल सलमान के कार्य समय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है।

'बैटल ऑफ गलवान' में एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन में भी सक्रिय

फिल्म 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है। इसमें सलमान न केवल मुख्य अभिनेता हैं, बल्कि सह-निमार्ता के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, वे फिल्म की एडिटिंग में भी शामिल हो रहे हैं और संभव है कि उन्हें फिल्म में सह-संपादक के रूप में भी क्रेडिट दिया जाए।

मुरुगादोस ने लगाए थे गंभीर आरोप

'सिकंदर' के बाद ए.आर. मुरुगादोस ने बताया था कि सलमान अक्सर रात 8 बजे सेट पर पहुंचते थे, जिसके कारण दिन की शूटिंग भी रात में करनी पड़ती थी। इससे बच्चों सहित कई कलाकारों और तकनीकी टीम को देर रात तक इंतजार करना पड़ता था। सलमान ने 'बिग बॉस 19' में इन आरोपों को स्वीकार किया था, लेकिन यह भी स्पष्ट किया था कि उस समय उनकी पसलियों में चोट थी, जिसकी वजह से उन्हें देर होती थी।